बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

# सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 110 ● नई दिल्ली ● सोमवार 09 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

### दिल्ली में बड़ा हादसा: बाथरूम में गीजर ब्लास्ट से भीषण आग, 1 व्यक्ति की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में एक इलेक्ट्रिक गीजर में विस्फोट के कारण घर में आग लगने से 50 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी पत्नी घायल हो गईं। पुलिस ने रविवार को बताया कि यह घटना शनिवार शाम पांच बजे हजरत निजामुद्दीन इलाके में हुई। इसने बताया कि पुलिस को एक घर में भीषण आग लगने की सूचना मिली और एक टीम तुरंत मौके पर भेजी गई। पुलिस को घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला और वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, बचाव अभियान के दौरान बाथरूम में मकान मालिक मोहम्मद सैयद निजामी और उनकी पत्नी फिदा निजामी (45) धुएं के कारण अचेत अवस्था में मिले।

# सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, इस नई योजना से बेहतर यातायात के साथ मिलेंगे हजारों रोजगार

नई दिल्ली।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (8 फरवरी) को रामलीला मैदान में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में दिल्ली की जनता को कई अहम संदेश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही नई ई-रिक्शा पॉलिसी लेकर आएगी. इससे न सिर्फ यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से बताया कि आज का दिन दिल्ली के लिए गर्व का दिन है. उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा और रविंद्र इंद्राज जैसे कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद हैं. मुख्यमंत्री ने इसे टीम वर्क और मजबूत सरकार का प्रतीक बताया.

**कार्यक्रम के दौरान क्या बोलीं सीएम रेखा गुप्ता?**

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 8 फरवरी 2025 को दिल्ली के राजनीतिक इतिहास का अहम दिन बताते हुए कहा कि इसी दिन दिल्ली की जनता ने 70 में से 48 सीटें देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिया. उन्होंने कहा कि यह जनादेश दिल्ली के विकास के लिए था. जनता ने एक ऐसी सरकार चुनी, जो काम करने में विश्वास रखती है.

**सीएम ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला**

इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यही रामलीला मैदान है, जहां कभी देशभक्ति की बातों के साथ अनशन हुआ, सादगी की कसमें खाई गईं, लेकिन बाद में सत्ता का दुरुपयोग हुआ. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 11 साल तक दिल्ली का विकास रुका रहा और खुद को दिल्ली का मालिक समझने की सोच ने शहर को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने 2025 में यह साबित कर दिया कि जो सत्ता में बैठा सकता है, उसे हटाना भी जानता है.

**अब विकास की नई रेखा खींची जा रही है- रेखा गुप्ता**

मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और अब विकास की नई रेखा खींची जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि सत्ता हमारे लिए भोग नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है. पर्यावरण और परिवहन को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि आज 500 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के बेड़े में शामिल की जा रही हैं, जिससे कुल ईवी बसों की संख्या 4000 से ज्यादा हो जाएगी. उन्होंने कहा कि यह देश के किसी भी राज्य में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस फ्लीट है.

**प्रदूषण को लेकर सरकार उठाने जा रही ये कदम**

सरकार का लक्ष्य है कि साल के अंत तक 7500 और वर्ष 2028 तक 14,000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएं.

इससे दिल्ली में प्रदूषण कम होगा और लोगों को सस्ती व बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री ने यमुना की सफाई, सीवर व्यवस्था और पानी की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि ये समस्याएं सरकार को विरासत में मिली हैं, लेकिन मौजूदा सरकार इन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने में जुटी है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में दिल्ली को साफ, सुरक्षित और आधुनिक राजधानी बनाया जाएगा.

### सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम, दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली में सरकार का एक साल पूरा होने पर रेखा गुप्ता सरकार का राम लीला मैदान में कार्यक्रम हो रहा है. इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद हैं. कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सत्ता हमारे लिए सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा का माध्यम है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 8 फरवरी 2025 का दिन ऐतिहासिक था क्यों की इस दिन दिल्ली की सत्तर में से 48 सीट पर बीजेपी के विधायक जीतकर सरकार बनाने का रास्ता पूरी तरफ से साफ कर दिया. और ये राम लीला मैदान कई संघर्ष और आंदोलन का गवाह है और ये वही राम लीला मैदान है जहां अन्ना आंदोलन हुआ और इसी राम लीला मैदान में कसम खाई थी की राजनीति में नहीं जाएंगे गाड़ी घर नहीं लेंगे. सीएम ने ये भी कहा, -इसी राम लीला मैदान ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया लेकिन दिल्ली की जानता ने उतार कर दिल्ली में कमल खिला दिया. 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और उसी दिन से दिल्ली विकास का पन्ना शुरू हुआ और उसी दिन से दिल्ली में हमारे 48 विधायक जनता की सेवा में जुट गए. दिल्ली की जितनी लटकी भटकी समस्याएं है उनका हल किया जाए. उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम भी एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 500 नई ई बसे जनता को समर्पित की जा रही है और 2028 तक दिल्ली में 14000 हजार बसे दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती नजर आये. दिल्ली की जो समस्या है पर्यावरण की उसमे भी ये बसे बहुत सहयोगी साबित होंगी. हम मेट्रो का विस्तार कर रहे है और दिल्ली मेट्रो के लिए हमने पांच हजार करोड़ का बजट तय किया.

### सीएम रेखा गुप्ता का बयान: दिल्ली में दौड़ेंगी सबसे ज्यादा ई-बसें, कहा- 365 दिन काम कर रही बीजेपी सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भरोसा जताने के लिए दिल्लीवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसी भरोसे के कारण सरकार उनके लिए वर्ष के 365 दिन निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) के मामले में अग्रणी शहर बनेगा, जहां सबसे अधिक ई-बसें संचालित होंगी। यह पहल दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा सरकार के पहले वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पीतमपुरा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में 500 ईवी बसों के लॉन्च से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जनता के भरोसे के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास की वजह से सरकार साल के 365 दिन काम कर रही है और दिल्ली जल्द ही सबसे अधिक ईवी बसों वाला शहर बनेगी। पिछले महीने सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की थी कि अगले तीन वर्षों में दिल्ली की 100 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन बसों को प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक फ्लीट में बदल दिया जाएगा। इसके लिए 11,000 इलेक्ट्रिक बसें लाने, चार्जिंग स्टेशन और नए बस डिपो बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है।

### जेएनयू में एबीवीपी ने प्रशासन को फिर घेरा, निष्कासन और भारी जुर्माने का विरोध, सीपीओ मैनुअल भी बना जड़

नई दिल्ली। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रशासन और छात्र संगठनों के बीच टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई ने निष्कासन और भारी जुर्माने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए तीखा विरोध दर्ज कराया है. अभाविप का कहना है कि छात्र आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीतियों का सहारा लिया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा. अभाविप जेएनयू ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वह निष्कासन और आर्थिक दंड को हथियार बनाकर छात्रों की आवाज को कुचलने की कोशिश कि जा रही है. संगठन का कहना है कि सक्रिय कार्यकर्ताओं को बाहर कर उनके शैक्षणिक भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो पूरी तरह अलोकतांत्रिक है. अभाविप ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की कायराना कार्रवाई से राष्ट्रवादी छात्र डरने वाले नहीं हैं. प्रशासनिक तानाशाही के विरोध में अभाविप कार्यकर्ताओं ने दमनकारी आदेशों की प्रतियां जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह प्रतीकात्मक विरोध नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ चेतावनी है जो छात्रों के अधिकारों को कुचलने पर आमादा है. संगठन ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा. CPO मैनुअल को लेकर अभाविप का रुख पहले दिन से सख्त और स्पष्ट रहा है. संगठन का कहना है कि यह मैनुअल जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय के स्वतंत्र और लोकतांत्रिक वातावरण के लिए घातक है और इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए. अभाविप ने आरोप लगाया कि प्रशासन अपनी अक्षमता छिपाने के लिए ऐसे काले कानूनों का सहारा ले रहा है. अभाविप जेएनयू ने यह भी स्पष्ट किया कि वह विरोध के नाम पर किसी भी तरह की अराजकता और तोड़-फोड़ के सख्त खिलाफ है.

### 11 साल बाद वकीलों की बल्ले-बल्ले: केंद्र सरकार ने बढ़ाई फीस, अब हर केस के मिलेंगे इतने हजार रुपये

नई दिल्ली। केंद्र सरकार का अदालतों में पक्ष रखने वाले वकीलों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने देशभर की अदालतों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की फीस बढ़ा दी है। यह बढ़ोतरी करीब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद की गई है। इस फैसले से उन हजारों वकीलों को फायदा होगा जो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं। कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग ने 5 फरवरी को एक अधिसूचना जारी की। इसमें वकीलों की बढ़ी हुई फीस की जानकारी दी गई है। यह फैसला लंबे समय से लंबित था और वकील इसकी मांग कर रहे थे। नई अधिसूचना के अनुसार, पैनल ए के वकील जो नियमित अपील और अंतिम सुनवाई वाले मामलों में पेश होंगे, उन्हें अब प्रति केस प्रति दिन 21,600 रुपये मिलेंगे। वहीं, पैनल बी और सी के वकीलों को 14,400 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले पैनल ए के वकीलों को 13,500 रुपये और पैनल बी और सी के वकीलों को 9,000 रुपये मिलते थे। सरकारी वकीलों की फीस में आखिरी बार अक्टूबर 2015 में बदलाव किया गया था। इसके अलावा, अन्य श्रेणियों के मामलों और मंत्रालयों के साथ बैठक करने की फीस भी बढ़ाई गई है। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि महंगाई और पेशेवरों को काम पर रखने की बढ़ती लागत को देखते हुए यह बढ़ोतरी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी।

## दिल्ली की हवा में मामूली राहत: राजधानी में 196 पहुंचा एक्यूआई, ठंड से भी मिली राहत; स्मॉग की परत अब भी बरकरार

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार सुबह सात बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 दर्ज किया गया, जो 'मॉडरेट' श्रेणी में है। यह शनिवार की तुलना में सुधार है, जब शाम चार बजे एक्यूआई 227 दर्ज किया गया था, जो 'खराब' श्रेणी में था। वहीं दिल्ली के मुंडका में सबसे अधिक एक्यूआई 266 दर्ज किया गया। इसके बाद पूसा 257, नरेला 247, रोहिणी 247, अशोक विहार 243, जहांगीरपुरी 242, वजीरपुर 239, नेहरू नगर 237, शादिपुर 236, बवाना 231, विवेक विहार 231, सिरीफोर्ट 222 और चांदनी चौक 220 एक्यूआई के साथ 'खराब' श्रेणी में रहे। श्री अरबिंदो मार्ग में सबसे कम एक्यूआई 126 दर्ज किया गया। इसके अलावा आईजीआई एयरपोर्ट 131, आया नगर 136, लोधी रोड 139, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 140, आईआईटी दिल्ली 141 और मंदिर मार्ग 145 एक्यूआई के साथ 'मॉडरेट' श्रेणी में रहे। सुधार के बावजूद शहर के कुछ हिस्सों में स्मॉग की हल्की परत बनी हुई है और कुल मिलाकर वायु गुणवत्ता अभी भी खराब बनी हुई है। रविवार के आंकड़े शनिवार जैसे ही रहे। शनिवार को आनंद विहार में एक्यूआई 260 और आरके पुरम में 237 दर्ज किया गया था, जो 'खराब' श्रेणी में था। दिल्ली के आईटीओ में रविवार सुबह एक्यूआई 223 के साथ 'खराब' श्रेणी दर्ज की गई, जबकि चांदनी चौक में एक्यूआई 232 रहा। आया नगर में एक्यूआई 151, आईजीआई एयरपोर्ट (T3) पर 138 और पूसा में 157 दर्ज किया गया, जो 'मॉडरेट' श्रेणी में रहे। एक्यूआई वर्गीकरण के अनुसार 0 से 50 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मॉडरेट', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बेहद खराब' और 401 से 500 'गंभीर' श्रेणी में आता है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज हवा में धुंध रहने की भी संभावना जताई गई है।

## 15 दिनों में फैसला नहीं तो..., ऑटो-टैक्सी चालक यूनियन ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चालकों की समस्याएं एक बार फिर सतह पर आ गई हैं. राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति ने केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कड़ा आक्रोश पत्र भेजते हुए दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की नीतियों को चालकों के लिए विनाशकारी बताया है. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगें नहीं मानी गईं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख हड़ताल शुरू की जाएगी. दिल्ली समेत देश भर के संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर ऑटो टैक्सी चालकों के हितो हेतु एकमत होकर ऐलान किया है कि अगर 15 दिनों के अंदर संगठन की मांगों को नहीं माना गया तो दिल्ली समेत देश भर के ऑटो टैक्सी चालक 23 फरवरी 2026 को 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे.

**गलत नीतियों से भुखमरी की स्थिति**

संगठन का आरोप है कि दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण राजधानी के ऑटो-टैक्सी चालक भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं. चालकों की शिकायत है कि उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है और हर स्तर पर उन्हें अपमान और दबाव का सामना करना पड़ता है.

**फिटनेस जांच फीस में चोरी-छुपे बढ़ोतरी का आरोप**

आक्रोश पत्र में कहा गया है कि नवंबर 2025 के अंत में बिना किसी अधिसूचना के ऑटो-टैक्सी वाहनों की फिटनेस जांच फीस में 800 रुपये की वृद्धि कर दी गई. इसके साथ ही वाहन फेल होने पर दोबारा जांच फीस में 600 रुपये का इजाफा किया गया. संगठन का कहना है कि इससे पहले अप्रैल 2025 में भी ऐसी ही बढ़ोतरी की गई थी, जिसे बाद में एनआईसी की गलती बताकर वापस लिया गया था.

**नए साल में फिर बढ़ी फीस, संगठन नाराज**

संगठन के अनुसार 5 जनवरी की शाम को एक बार फिर बिना किसी आधिकारिक सूचना के फिटनेस जांच फीस में 800 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई. इसे वाहन कैटेगरी को लेकर बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला बताते हुए संगठन ने तत्काल प्रभाव से इसे वापस लेने की मांग की है.

**एग्रीगेटर कंपनियों को छूट, चालकों पर सख्ती**

राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति ने आरोप लगाया कि 2 जनवरी 2026 को दिल्ली सरकार ने ऑटो-टैक्सी संगठनों को बुलाने के बजाय ओला, उबर और रैपिडो जैसी मोबाइल ऐप कंपनियों के साथ बैठक कर निजी कारों को सवारी ढोने की अनुमति दी. संगठन का सवाल है कि जब निजी वाहन सवारी ढो सकते हैं तो कमर्शियल वाहनों पर इतने सख्त नियम और पाबंदियां क्यों.

**चालान, जब्ती और उत्पीड़न का दर्द**

चालकों ने बताया कि कभी खाना खाते समय चालान, कभी सवारी के इंतजार में चालान और कभी जबरन फोटो खींचकर चालान काटे जाते हैं. इसके अलावा परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट टीम द्वारा बिना कारण वाहन जब्त किए जाते हैं, जिनकी रिहाई के लिए भारी जुर्माना और शुल्क देना पड़ता है. संगठन का कहना है कि ऑटो-टैक्सी चालक सिर्फ अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए सड़कों पर मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें मारपीट, गाली-गलौज और शोषण झेलना पड़ता है.

## 'ऑनलाइन गेम्स बैन करो' के नारों से गूंज उठी दिल्ली, बच्चों के भविष्य को लेकर सड़क पर उतरा नेशनल अकाली दल

नई दिल्ली।

ऑनलाइन व मोबाइल गेमिंग को लेकर नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा की अध्यक्षता में सैकड़ो सदस्यों ने वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सभी ऑनलाइन गेम्स बैन करो, बैन करो बैन करो ऑनलाइन गेमिंग बैन करो, ऑनलाइन गेम बनी बच्चों की हथियारण, ऑनलाइन गेम्स के जरिए बच्चों का भविष्य मत बिगड़ो जैसे नारे लगा रहे थे और उनके हाथों में ऐसे बैनर भी पकड़े हुए थे। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि, बड़े दुख की बात है ऑनलाइन गेम में बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है और अब तो जानलेवा भी साबित हो रही है इसमें बच्चे इतने लिप्त हो जाते हैं कि इनको मना करो तो बच्चे या तो खुद आत्महत्या कर लेते हैं या

फिर अपने परिवार के ऊपर किसी न किसी तरह से हमला कर देते हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि, इसको लेकर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और उन एप्स के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए जो बच्चों को आपराधिक घटनाओं की ओर धकेल रही हैं। उन्होंने सरकार से सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए एक आयु सीमा तय करने की भी मांग की। पम्मा ने तर्क दिया कि, कई देशों में 16 वर्ष से पहले बच्चे सोशल मीडिया से नहीं जुड़ सकते। साथ ही स्कूलों को भी यह हिदायत देनी चाहिए वह बच्चों को मोबाइल पर होमवर्क का कार्य न दे। क्योंकि बच्चों के पास एक बहाना हो जाता है वह स्कूल का कार्य कर रहे है और इसी के आड़ में वह किसी न किसी ऐप से जुड़ जाते हैं।

पम्मा ने उन्होंने परिवार के लोगों से भी अपील की बच्चों को पार्कों में भेजें और उनके मोबाइल पर जरूर नजर रखें वह किस ऐप से जुड़े हुए हैं ताकि बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के खतरों से बचाया जा सके। परमजीत सिंह पम्मा व नेशनल अकाली दल महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना धवन, रश्मीत कौर बिंद्रा ने ऑनलाइन बेटिंग और जुए वाले गेम्स पर चिंता जताई है, जो लत लगाने वाले होते हैं और लोगों को आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे गेम्स पर रोक लगनी चाहिए। हरमिंदर पाल सिंह बक्शी, इंद्रजीत सिंह अष्ट, विक्रांत मोहन ने कहा सरकार ऑनलाइन गेम्स को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जिसमें बच्चों का भविष्य हम बचा सके। इस अवसर पर राजेश चौहान, रूबी जिंदल, बलबीर सिंह, बलविंदर सिंह सरना, जसविंदर सिंह सभरवाल, जसवीर सिंह सरना, आफरीन, वरिंदर आर्य, सुनीता अरोड़ा, रूप सिंह गोसाई, रिदम चड्ढा, रोजी विरमानी, सुखविंदर सिंह,पंकज छाबड़ा, अमर गुप्ता, अजय मेहरा, तरुण सोनी सहित अनेक लोग शामिल थे जिन्होंने ऑनलाइन गेम बैन करने की मांग की।

## गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, दिल्ली में भव्य शुकराना कीर्तन समागम का आयोजन

नई दिल्ली ( इंद्रजीत सिंह )गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, नई दिल्ली स्थित लखी शाह बनजारा हॉल नंबर-2 में एक भव्य एवं आध्यात्मिक रूप से ओतप्रोत शुकराना कीर्तन समागम का आयोजन किया गया।

यह पावन समागम श्री गुरचरण सिंह (राजू) एवं श्रीमती अमरजीत कौर (लवली) के सान्निध्य एवं संरक्षण में श्रद्धा एवं गरिमा के साथ संपन्न हुआ।

इस पवित्र अवसर पर अनेक गणमान्य अतिथियों एवं सार्वजनिक जीवन की प्रतिष्ठित हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रमुख रूप से सरदार हरमीत सिंह कालका, महासचिव, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (DSGMC); सरदार जगदीश सिंह काहलोन, अध्यक्ष, DSGMC; श्री वीरेंद्र सचदेवा, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी (दिल्ली); श्री जे.पी. अग्रवाल, पूर्व सांसद; श्री महाबल मिश्रा, वरिष्ठ राजनीतिक नेता; अनेक विधायक तथा श्री अरविंदर सिंह लवली, अध्यक्ष, यमुना पार विकास बोर्ड

उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त श्री हारून यूसुफ, पूर्व मंत्री, दिल्ली सरकार; श्री अनिल चौधरी, पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (DPCC); प्रख्यात उद्योगपति श्री गुरिंदर सिंह सिक्का; श्री नसीब सिंह, पूर्व विधायक; श्री सुनील सिंघवी, अध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रेड फ्रेंडशिप; डॉ. हरि दत्त शर्मा; एडवोकेट हरीश गोला; श्री पारस शर्मा , पिंकी (ओनर, हीरा स्वीट्स); तथा श्री विजय शंकर चतुर्वेदी, अध्यक्ष, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी समागम की शोभा बढ़ाई। समागम के दौरान सभी गणमान्य अतिथियों का श्री गुरचरण सिंह (राजू) द्वारा शॉल भेंट कर सम्मानपूर्वक अभिनंदन किया गया। रागी जत्थों द्वारा प्रस्तुत भावपूर्ण कीर्तन ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कीर्तन की मधुर धुनों से संगत में आध्यात्मिक आनंद, कृतज्ञता एवं आपसी एकता की भावना का संचार हुआ।

## अमेरिका से कृषि आयात !

**भारत** और अमेरिका के बीच हो रहे व्यापार समझौते पर दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट हो गया है कि देश की मोदी सरकार ने अपने कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों को पूरी तरह संरक्षित किया है और अमेरिका में भारतीय कृषि जन्य उत्पादों के निर्यात को नई ऊंचाई पर पहुंचाने की गरज से इनमें से कई पर अमेरिका को शून्य शुल्क दर लगाने पर भी मना लिया है। इस प्रकार भारत में इस करार को लेकर विपक्ष व कुछ अन्य क्षेत्रों द्वारा जो आशंका जताई जा रही थी वह पूर्ण रूपेण निर्मूल साबित हुई है जिसके लिए वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयल व मोदी सरकार बधाई की पात्र है। इसके साथ ही संयुक्त वक्तव्य में घोषणा की गई है कि भारत अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए अपने बाजार नहीं खोलेगा तथा लघु व मध्यम क्षेत्र में उत्पादित होकर अमेरिका में निर्यात होने वाले कुछ उत्पादों पर भी अमेरिका शुल्क दर शून्य रखेगा। कृषि के क्षेत्र में केवल पशुओं के ऐसे आयात को खोला गया है जिसकी भारत के बाजार में मांग है और उससे भारतीय किसानों को लाभ हो सकता है। जहां तक दोनों देशों के बीच 500 अरब डॉलर के अमेरिकी निर्यात कारोबार का लक्ष्य है तो इसे अगले पांच वर्षों में बढ़ाकर इस सीमा तक किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वाणिज्यिक करार में भारत अमेरिका से ऐसी शुल्क छूट लेने में कामयाब रहा है जिससे भारत का निर्यात कारोबार लगातार बढ़ता रहे। विशेषकर कृषि क्षेत्र में भारत के निर्यात कारोबार को इस समझौते के बाद नई गति मिल सकती है। भारत के किसानों को इस समझौते के बाद सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उनकी कृषि उपजों का घरेलू बाजार में भाव नीचे नहीं गिरेगा और दूसरी तरफ भारतीय उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा तथा ऐसी वस्तुओं की भारत में सप्लाई बढ़ेगी जिनका उत्पादन भारत में कम होता है। वैसे अभी विभिन्न उत्पादों की सिलसिलेवार सूची तैयार होने में कुछ समय और लगेगा मगर करार को लेकर देश के कृषि क्षेत्र में जो आशंकाएं फैलाई जा रही थीं उन पर पानी फिर गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि बिना समझौता हुए भी दोनों देशों के बीच कृषि उत्पादों के आयात-निर्यात कारोबार में पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि हो रही है और अमेरिका का निर्यात अपेक्षाकृत रूप से बढ़ रहा है। हालांकि भारत-अमेरिका को अपने कृषि उत्पादों का निर्यात अमेरिका से आयात किये जाने के मुकाबले अधिक कर रहा है। इसकी मूल वजह यह है कि समझौते की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यह लिखा कि अमेरिका भारत को अब 500 अरब डॉलर की मूल्य की विभिन्न वस्तुओं का निर्यात करेगा और इनमें कृषि उत्पादों का क्षेत्र भी खोल दिया जायेगा। ट्रम्प के इस कथन में केवल इतनी ही सच्चाई थी कि दोनों देशों के बीच में घोषित प्रतिस्पर्धी नई शुल्क दर 18 प्रतिशत के बाद आपसी कारोबार में वृद्धि होगी। दूसरी ओर भारत के वाणिज्यमन्त्री श्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया था कि भारत अपने कृषि व डेयरी उद्योग के हितों को पूरी तरह संरक्षित रखते हुए ही व्यापार समझौते को अन्तिम रूप देगा। भारत अमेरिका से जिन कृषि जन्य उत्पादों का आयात करता है उनमें सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट के अलावा इथनोल, कपास व सोयाबीन तेल मुख्य रूप से शामिल है। जबकि भारत से अमेरिका को निर्यात किये जाने वाले उत्पादों में समुद्री खाद्य (मछलियां) मसाले, चावल, संसाधित फल व सब्जियां, बेक्ड फूड, आवश्यक तेल, चीनी, वनस्पति तेल व तैयार खाद्य (प्रिपेयर्ड फूड) शामिल हैं। भारत ने वर्ष 2025 के दौरान अमेरिका को कुल 591 करोड़ 41 लाख डॉलर मूल्य की कृषि वस्तुओं का निर्यात किया जबकि इसका आयात केवल 285 करोड़ 37 लाख करोड़ डॉलर का रहा। इससे यह नतीजा निकलता है कि कृषि कारोबार खाता भारत के पक्ष में है। बेशक अमेरिका चाहता था कि भारत इथनाल जैसे उत्पाद का आयात अपने पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए भी खोले, जिससे इसका उपयोग पेट्रोल मिश्रण में हो सके क्योंकि भारत अभी तक इथनाल का आयात केवल औद्योगिक जरूरतों के लिए ही करता है। अमेरिका में इथनाल का उत्पादन मक्का से होता है और वहां पर मक्का का उत्पादन बहुत अधिक होता है। इसकी पैदावार भी अमेरिका में प्रति हैक्टेयर के हिसाब से पूरी दुनिया में सर्वाधिक है जबकि भारत में भी इथनाल का उत्पादन कृषिजन्य कच्चे माल जैसे गन्ना व चावल भूसी व मक्का से होता है। अतः भारत को अपने इस क्षेत्र को संरक्षित रखना था और करार में ऐसा ही हुआ। इथनाल का केवल एक उदाहरण है जो हमें यह बताता है कि भारत ने किस प्रकार अपने कृषि क्षेत्र को संरक्षित रखा। कृषि कारोबार के क्षेत्र में हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत में प्रति हैक्टेयर फसल उत्पादन अमेरिका के मुकाबले आज भी बहुत कम है। अत: अपने किसानों के हितों के संरक्षण के लिए हमें ऐसे कदम उठाने होंगे कि घरेलू बाजार में उनकी उपज के दाम हर हालत में लाभप्रद बने रहें। इसी प्रकार हमें डेयरी उद्योग को भी देखना होगा। अमेरिका में गायों को मांसाहारी (सामिष) भोजन भी दिया जाता है और उनसे दुग्ध उत्पादन सस्ते में किया जाता है जबकि भारत में प्रतिलीटर दूध उत्पादन की लागत अधिक आती है। इसके बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। अत: समझौते में अमेरिकी डेयरी उत्पादों का भारत में प्रवेश निषेध होगा। दरअसल व्यापार समझौता इस प्रकार होना चाहिए जिससे भारत के किसानों की उपज के मूल्य घरेलू बाजार में किसी भी रूप में अमेरिकी सामान से कम न रह सकें। इस मामले में कृषि मन्त्री श्री शिवराज सिंह ने भी कहा है कि भारतीय किसानों के हित सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे और इन पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दी जायेगी। परन्तु भारत में अमेरिकी कपास की आवक में भी वृद्धि हुई है। विगत अगस्त महीने से दिसम्बर महीने तक भारत सरकार ने जीरो शुल्क दर पर अमेरिकी कपास के आयात की अनुमति दी थी। मगर 1 जनवरी 26 से यह शुल्क दर 11 प्रतिशत कर दी गई। यही स्थिति सोयाबीन तेल में भी रही हालांकि इसमें शुल्क ढांचा दूसरा था। इस मामले में अमेरिकी राजनेताओं के वक्तव्य भारत में चिन्ता पैदा कर रहे थे क्योंकि वे कह रहे हैं कि समझौता होने के बाद भारत का बहुत बड़ा बाजार अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खुल जायेगा और इस मद में दोनों देशों के बीच हो रहा कारोबार अन्ततः अमेरिका के घाटे को पाट देगा।

## मीठा जहर : ऑनलाइन गेमिंग

**मोबाइल** फोन और ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों और युवाओं के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। जिस तकनीक को शिक्षा की जानकारी का सशक्त माध्यम माना गया था, वही अब बच्चों की मानसिक और शारीरिक हैल्थ के लिए खतरा बन रही है। पबजी और ब्लू व्हेल के बाद अब कोरियन गेम बच्चों तथा युवाओं की जान ले रही है। अत्यधिक मोबाइल और गेमिंग का उपयोग बच्चों के व्यवहार, सोच और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा नकारात्मक असर डाल रहा है। हालत यह है कि बच्चे, किशोर और युवा आत्महत्या जैसे कदम उठाने लगे हैं तो कारण गेमिंग की लत ही है। विशेषज्ञ इस गेमिंग के चस्के को मीठा जहर करार दे रहे हैं और बच्चों को बचाने की चेतावनी दे रहे हैं। गाजियाबाद की सोसायटी में ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हुई तीन बहनों निशिका, प्राची और पाखी ने जिस तरह 9वीं मंजिल से कूदकर जान दी यह एक चौंका देने वाला वाकया है और हमें चेतावनी दे रहा है कि बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के साथ-साथ मोबाइल की लत मत लगने दें। मेरा यह भी मानना है कि युवाओं की अस्वाभाविक मौतें नहीं होनी चाहिए। जैसा कि पहले नोएडा में सड़क पर गड्ढे में गिरकर एक इंजीनियर युवराज की मौत हुई। अब ताजा वाकया जनकपुरी में एक बैंक मैनेजर की गड्ढे में गिरकर हुई दर्दनाक मौत का है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारों व प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा।वे तीनों बहनें जिस कोरियाई गेम की दिवानी रही, क्यों कोरियन गेम उनको जान से भी प्यारी बन गयी, यह सब इन बच्चियों के 8 पन्नों का सुसाइड नोट सब कुछ बयान करता है। बच्चों को करोना अवधि अर्थात 2019-20 में भी मोबाइल की लत थी। देखते ही देखते वे तीनों बहनें सोते-जागते एक ही मोबाइल से कोरियन ऑनलाइन गेम खेला करती थीं। इसके प्रति बढ़ते क्रेज ने उन्हें क्रेजी कर दिया। वे अपने आपको कोरियाई समझने लगीं। विशेषज्ञ बताते हैं कि गेमिंग ऐप में बच्चे किसी भी मामले में जब कुछ टॉस्क करते हैं तो वे अपने आपको वैसा ही समझते हैं जो टास्क उनको दिया जाता है। अपने आपको बहुत एक्सपर्ट मानना या जो गेम हमने खेली उसे कोई जीत नहीं सकता, केवल हम ही जीत सकते हैं, यह सोच बच्चों में पागलपन की हद तक बैठी हुई है। हम ऐसे भावनात्मक समर्थन को सही नहीं ठहरा सकते लेकिन बच्चे में परिवर्तन आ रहे हैं तो इसे ध्यान में रखकर सतर्क जरूर होना चाहिए। वे तीन बच्चियां तो चली गयी लेकिन आज भी भाई-बहन या साधारण और हाईफाई घरों के बच्चे सैकड़ों ऑनलाइन गेमिंग के दिवाने हैं। माता-पिता को उन पर नजर तो रखनी ही चाहिए लेकिन उन्हें समझाने-बुझाने का कोई ठोस तरीका अपनाना चाहिए और यह सब एकदम प्रेम से होना चाहिए। आज गेमिंग को बच्चे मनोरंजक तकनीक मानकर खेल रहे हैं। वे इस लत की दिशा में चल पड़े है जिसके परिणाम बड़े घातक निकल रहे हैं। हालांकि बच्चों की सुसाइड का कारण बच्चों द्वारा लिखे पत्र में बताया गया है लेकिन इस ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए माता-पिता कुछ और विकल्प ढूंढ़? सकते हैं। मैं ये सब बातें सोशल मीडिया के आधार पर जो लोग शेयर कर रहे हैं उसी के अनुरूप बोल रही हूं। ऑनलाइन गेमिंग के तौर-तरीके बच्चों में लत पैदा करते हैं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा टॉस्क देकर विजेता बनने के लिए प्रलोभन दिये जाते हैं और उसकी तुलना कभी किसी कोरियाई?स्टार से की जाती है जो कभी फांस के सुंदर युवक-युवती से या फिर ब्रिटेन के गोरे चिट्टे बच्चों से की जाती है। यह फंटेसी बच्चों को एक आकर्षण तो लगती है लेकिन वैसा बनने की चाहत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं जब इससे पहले कई बार ऑनलाइन गेमिंग और रील मेकिंग को लेकर कितने ही बच्चों के साथ हुए हादसों का जिक्र करती थी तो हैरान होती थी कि कहीं आगे चलकर यह मामला और खराब न हो जाए लेकिन दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि हम इस दिशा में कोई हल नहीं ढूंढ पा रहे। मुझे याद है जब हम रामायण, श्रीमद्भगवत गीता पढ़ते थे या फिर सन् 1980 के दौर में टीवी पर रामायण और महाभारत धारावाहिक का दौर चला तो भगवान की लीलाओं और उनके प्रेरक प्रसंगों को देखकर हम उनसे शिक्षा लेते थे जो आगे चलकर संस्कार बन गए। बाद में इन सीरियल की तर्ज पर कॉमिक्स भी बनें और वे भी बहुत प्रेरणादायी थे लेकिन यह दौर इतनी जल्दी चला जायेगा और इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी आ जायेगी, यह हमने नहीं सोचा था। अब टेक्नोलॉजी आ ही गयी है तो नई पीढ़ी इस पर अपना हक समझती है लेकिन इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के तौर-तरीके और कंट्रोल करने के लिए भी कुछ करना ही होगा। मेरी कितनी ही एक्सपर्ट्स से बात होती है कुछ लोग मुझसे विचार पूछते हैं तो मेरा यही कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों की मानसिकता को बदल डालती है। वे भावनात्मक रूप से एक ऐसी अलग दुनिया में खुद को ले जाते हैं कि जहां उन्हें आनंद ही आनंद इस गेम में मिलता है। उनका खाना-पीना उनकी नींद, उनकी पढ़ाई सब खत्म हो जाता है। आपस में बातचीत भी इसी ऑनलाइन गेमिंग पर होती है। वक्त आ गया है कि इसके लिए सबको मिलकर कुछ करना होगा। बच्चे सबके साझे है लेकिन देश का भविष्य भी है, लिहाजा कुछ करना ही होगा ताकि फिर गाजियाबाद जैसा कांड न हो पाए।

**सम्पादकीय...**

## कल्याणकारी बजट

मैं पकोड़े खा रहा था और सोच रहा था कि कोई पकोड़े की ठेली वाला तो इस मौसम में घर पर ही बैठा होगा। एक तो कड़के की ठंड और ऊपर से ऐसा मौसम। घर से निकलें तो निकलें कैसे। और निकल भी जाये तो उसकी ठेली का चूल्हा कैसे जलेगा, उसकी कढ़ाई कैसे चढ़ेगी। और अगर ठेली का चूल्हा नहीं जलेगा तो घर का चूल्हा भी ठंडा ही रहेगा। इस पकोड़े तलने के रोजगार को सरकार जी ने रोजगार तो डिक्लेअर कर ही दिया है पर मैं सोचता हूं पकोड़े तलने और इस तरह के अन्य कामों को राष्ट्रीय रोजगार डिक्लेअर कर देना चाहिए। जब मैं पकोड़े तलने वालों, चाय बनाने वालों, मटर कुलचे बेचने वालों, राजमा चावल और कढ़ी चावल बेचने वालों की संख्या देखता हूं तो सचमुच में आश्चर्य होता है कि इतने सारे लोग इस तरह के रोजगार में लगे हुए हैं। एक फरवरी का दिन बजट का दिन भी होता है। इस दिन केंद्र सरकार अपना वार्षिक बजट पेश करती है। बताती है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जायेगा। वैसे सब को पता है, पहले से ही पता है, सरकार न बताए तो भी पता है कि पैसा जनता की जेब से आएगा और नेताओं, ठेकेदारों, अफसरों और 'परम मित्रों' की जेब में जायेगा। बस हर बार यह फिगर, पैसे की संख्या अलग होती है। हर बार पिछली बार से अधिक पैसे का लेनदेन होता है। बजट में तो बस वह संख्या बताई जाती है। और हाँ, बजट में यह भी बताया जाता है कि किस किस विभाग के लोगों को मिल बाँटने, खाने पीने के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा। हर बार की तरह इस बार भी रखा बजट का अधिक कल्याण हुआ। यह अच्छा ही किया। जब चारों ओर दुश्मनों से घिरे बैठे हों तो हथियार खरीदने ही पड़ते हैं। हमने पड़ोसियों से इतनी दुश्मनी पहले कभी नहीं पाली थी जितनी आज पाली हुई है। वैसे सरकार मानती है कि लड़ाई के लिए हथियार आधुनिक और टिकाऊ जरूरी हैं। सैनिक तो सिर्फ चार साल के लिए भी भर्ती किए जा सकते हैं। कल्याण तो एक्सप्रेस वे का भी हो रहा है। अधिक से अधिक संख्या में बनते जा रहे हैं। इनको बनाने में पैसा अधिक खर्च होता है तो जाहिर है खाया भी अधिक जाता है। नेताओं, ठेकेदारों, अफसरों का अधिक कल्याण होता है और जनता भी खुश हो जाती है। जिस सड़क पर रोज चलना है, साईकिल और स्कूटी चलानी है, वह टूटी फूटी पड़ी रहे, उसमें सैकड़ों गड्ढे हों पर जिस पर से दो चार साल में एक बार गुजरें, भारी भरकम टोल दे कर गुजरें, वे सड़कें खूब चौड़ी, गड्ढा मुक्त होनी चाहिएं। सरकार जी यह सोचते हैं और हम भी इसी में अपना कल्याण मानते हैं। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कल्याणकारी चीजों का कल्याण नहीं हुआ। क्यों भई, सरकार ही सब कुछ करे। सरकार जी ही सबका कल्याण करें। पढ़ कर के कौन सा तीर मार लोगे, कौन सा पहाड़ तोड़ लोगे। और वैसे भी तीर मारने के लिए, पहाड़ तोड़ने के लिए पढ़ाई कौन सा जरूरी है। बिल गेट्स कोई खास पढ़ा लिखा नहीं है और न ही एलेन मस्क। और दूर क्यों जाना। सरकार जी ही कौन सा पढ़े हैं। जीवन में उन्नति के लिए पढ़ाई कोई जरूरी नहीं है।

## भाजपा ने तो संसद में हमेशा उछाले हैं अख़बार

अनिल जैन

**लोकसभा** में बीते सोमवार को बड़ा विवाद हुआ कि राहुल गांधी कैसे एक बिना छपी हुई किताब के अंश पढ़ कर मुद्दा उठा रहे हैं। संसद के कामकाज के नियम 349 के हवाले से कहा गया कि संसद में किसी बिना छपी हुई किताब या अखबार या पत्रिका की कतरन के आधार पर चर्चा नहीं की जा सकती है। हालांकि स्पीकर ओम बिरला को यह कहते भी सुना गया कि किसी भी किताब या अखबार के आधार पर मुद्दे नहीं उठाए जा सकते। राहुल कोई 45 मिनट तक बोलने का प्रयास करते रहे और अंत में इतने परेशान हो गए कि उन्होंने तंज करने के अंदाज में स्पीकर से पूछ कि वे बता दें कि नेता प्रतिपक्ष को क्या बोलना चाहिए। हैरानी की बात है कि पत्रिका और किताब के आधार पर मुद्दे उठाने से रोकने की कोशिश कर रही भाजपा ने विपक्ष में रहते सबसे ज्यादा राजनीति इसी आधार पर की है। इंदिरा और राजीव गांधी के जमाने से लेकर नरसिंहराव और मनमोहन सिंह के जमाने तक भाजपा के नेता अक्सर अखबारों में छपी खबरों के हवाले से संसद में हंगामा करते थे। बोफोर्स का मामला तो स्वीडिश रेडियो ने खोला था और उसके बाद अखबारों ने यह मुद्दा उठाया था। उस समय भाजपा और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने लगातार अखबारों में और खासकर 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी खबरों के आधार पर संसद में मुद्दे उठाए थे। नरसिंहराव और मनमोहन सिंह के समय भी तमाम कथित घोटाले अखबारों में छपी खबरों के आधार पर ही संसद में उठाए गए थे। लेकिन अब भाजपा को पत्रिका और किताब से समस्या है।

**नकदी बांटने की योजनाएं कब तक?**

इस बार के आम बजट और उससे पहले आए आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान इस बात पर खूब चर्चा हुई है कि नकदी बांटने की योजनाएं कब तक चलती रहेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने इसके आंकड़े दिए हैं। हालांकि एक साल पहले आर्थिक सर्वेक्षण में इस किस्म की योजनाओं की तारीफ की गई थी। लेकिन इस बार यह चिंता जताई गई है कि इस किस्म की योजनाओं से राजकोष पर बहुत बोझ बढ़ रहा है और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास की अनेक योजनाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। असल में एक अनुमान के मुताबिक देश की कई राज्य सरकारें मिल कर सिर्फ महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं में हर साल दो लाख करोड़ रुपए बांट रही हैं। अभी कई राज्यों ने ऐसी योजना शुरू नहीं की है। अगर देश के सभी राज्य ऐसी योजना शुरू कर दे तो यह राशि चार लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। महिलाओं के अलावा दूसरे कई और समूहों को भी नकद पैसे दिए जा रहे हैं। इसीलिए अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि योजना की घोषणा के साथ ही सनसेट क्लॉज भी लगाया जाना चाहिए। इसमें यह बता दिया जाना चाहिए कि योजना कितने दिन तक चलेगी। उस सीमा के बाद इसे समाप्त कर देना चाहिए। नकद बांटने की योजना को अनंतकाल तक चलाए रखना देश के लिए ठीक नहीं है।

**जनगणना में भी समस्या आएगी!**

मतदाता सूचियों को विशेष गहन पुनरीक्षण तो अभी तक संदेह और विवादों के घेरे में है ही और अब जनगणना को लेकर भी एक महत्वपूर्ण सवाल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि जाति जनगणना के लिए जाति प्रमाणपत्र या जाति को प्रमाणित करने वाला कोई एक प्रमाणपत्र अनिवार्य किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि जाति गणना के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे कुछ जातियों के आंकड़े असाधारण रूप से ज्यादा और कुछ के कम हो सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन जनगणना फॉर्म भरने के समय भी कोई दस्तावेज अनिवार्य किया जाना चाहिए। अगर कोई दस्तावेज अनिवार्य किया जाता है तो उसमें निर्धारित से ज्यादा समय लगेगा। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में उठाए गए बिंदुओं से सहमति जताई है। इतना ही नहीं सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता आकाश गोयल की तारीफ की है कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया और अदालत का ध्यान इस ओर खींचा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और याचिका में उठाए गए बिंदुओं से सैद्धांतिक सहमति जताई। अदालत को भी लग रहा है कि अगर कोई दस्तावेज अनिवार्य नहीं किया गया तो संतुलन बिगड़ सकता है। हालांकि अभी अदालत ने मामला जनगणना करने वाली संस्था पर छोड़ा है कि वह इस चिंता का क्या हल निकालती है।

**ममता बनर्जी क्या अब भी अकेले चलेंगी?**

संसद के बजट सत्र में विपक्षी पार्टियों के बीच कमाल की एकजुटता बनी है। विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां राहुल गांधी के साथ खड़ी है और उनके उठाए मुद्दों का समर्थन कर रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद अब भी अलग मुद्दा उठाए हुए हैं। इसका तात्कालिक कारण ममता बनर्जी का दिल्ली पहुंचा रहा। दो फरवरी को उन्हें चुनाव आयोग से मिलना था, जहां उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को खूब आड़े हाथों लिया। अगले दिन तीन फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुईं। उनका दावा है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिये लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस मसले पर चुप्पी साधी है। दरअसल कांग्रेस को पता है कि पश्चिम बंगाल में उसका बहुत कुछ दांव पर नहीं है। इसलिए उसके नेता एसआईआर का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को शिकायत है कि ममता बनर्जी जान बूझकर राहुल गांधी की अनदेखी करती हैं। राहुल जो मुद्दे उठाते हैं, उन पर वे चुप रह जाती हैं। इसके साथ ही बंगाल के बाहर दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए ममता बनर्जी काम करती है। इसीलिए कांग्रेस चुप है। अब तृणमूल के नेता चाहते हैं कि किसी तरह से संसद सत्र के दौरान कांग्रेस को तैयार किया जाए कि वह एसआईआर के मुद्दे पर बोले। यह तभी होगा, जब ममता बनर्जी कांग्रेस और राहुल के मुद्दों का समर्थन करेंगी।

**कहां है कांग्रेस का मनरेगा बचाओ' आंदोलन?**

कांग्रेस पार्टी ने काफी सोच-विचार कर और योजना बना कर पिछले महीने मनरेगा बचाओ' आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने कई बार कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने एकजुट होकर आंदोलन किया था, उसी तरह मनरेगा को समाप्त करके 'जी राम जी कानून' लाने के खिलाफ मजदूर एकजुट होंगे। राहुल का दावा है कि केंद्र सरकार को यह कानून भी वापस लेना होगा, जैसे उसने कृषि कानून वापस लिए थे। लेकिन सवाल है कि क्या इन कानून को वापस लेने के लिए उसी तरह का आंदोलन हो रहा है, जैसा किसानों ने किया था? हजारों किसानों ने भीषण सर्दी, गरमी और बरसात का सामना करते एक साल तक दिल्ली की घेराबंदी करके रखी थी। उस दौरान सैकड़ों किसानों की जान गई थी। तब सरकार ने वह कानून वापस लिया था। लेकिन मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है वह कहीं दिख नहीं रहा है। 10 जनवरी से शुरू हुआ आंदोलन 15 फरवरी तक चलना था। लेकिन एक महीना पूरा होने से पहले ही इसकी चर्चा बंद हो गई है। शुरू में कुछ दिन तो कांग्रेस के नेताओं ने जिला मुख्यालयों आदि में प्रदर्शन वगैरह किया लेकिन अब वह भी बंद है। अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि नया कानून वापस हो तो इस तरह ढीले ढाले अभियान से वह नहीं हो पाएगा। इसके लिए सुनियोजित आंदोलन की जरूरत पड़ेगी।

## बजट 2026-27:आर्थिक समस्याएं और औंधी रणनीति

**अब** जबकि पूंजीवाद का सर्वोच्च दूत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तक भारत के जीडीपी के अनुमानों की विश्वसनीयता पर संदेह जता चुका है, ठीक-ठीक बजट के आंकड़ों का, जो जीडीपी के एक खास स्तर तथा रुपयों में जीडीपी में एक खास वृद्धि दर को मानकर चलने पर आधारित होते हैं, कोई खास अर्थ ही नहीं रह जाता है। वास्तव में वर्तमान बजट में, करारोपण संबंधी अनेक कदमों की घोषणा करते हुए, इसके अनुमान तक देने की जहमत नहीं उठायी गयी है कि इन कदमों से राजस्व में कितनी कमी या बढ़ोतरी होने जा रही है। फिर भी बजट के आंकड़ों से हम इस बजट की रणनीतिक दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं और हैरानी की बात नहीं है कि यह रणनीतिक दिशा, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में, एक पूरी तरह से विकृत रणनीति है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याएं इस प्रकार हैं- आर्थिक असमानता में बेतहाशा बढ़ोतरी, जिसका परिमाण पिछले सौ वर्षों के दौरान, किसी भी समय में इतना ज्यादा नहीं था; शुद्ध गरीबी में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है, जिसे शुरुआत में योजना आयोग द्वारा दैनिक कैलोरी आहार के मानक के आधार पर परिभाषित किया था; और बेरोजगारी में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी मार में अब देश के शिक्षित युवाओं का विशाल हिस्सा भी आ चुका है। इन समस्याओं का एक साझा समाधान यह है कि आम लोगों के हाथों में बड़े पैमाने पर क्रय शक्ति पहुंचायी जाए। लेकिन, अगर जीडीपी के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटे को नहीं बढ़ाना हो तो, इसे अमीरों की कीमत पर कर एकत्र करने के खासे बड़े प्रयास के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। इससे, उपभोग की मांग में बढ़ोतरी के रास्ते, अर्थव्यवस्था में सकल मांग का स्तर बढ़ेगा और यह उत्पाद तथा रोजगार में बढ़ोतरी की ओर और गरीबी में कमी की ओर भी ले जाएगा। इससे आय की असमानता भी घटेगी क्योंकि अमीरों की करोपरांत आय का स्तर, अन्यथा जो होता उससे घटकर होगा। लेकिन, बजट रणनीति की विकृति, इसमें निहित है कि उसमें जो दिशा ली जानी चाहिए थी उससे ठीक उल्टी दिशा ली गयी है। जीडीपी के हिस्से के तौर पर कुल कर राजस्व में कोई बढ़ोतरी होने के बजाए, मामूली गिरावट ही हुई है और यह 2023-24 तथा 2024-25 के 11.5 फीसद तथा 2025-26 (संशोधित अनुमान) के 11.4 फीसद से कुछ घटकर, 2026-27 में 11.2 फीसद रह गया है। और बताया गया है कि इसके साथ ही राजकोषीय घाटा 2024-25 के 4.8 फीसद और 2025-26 (संशोधित अनुमान) के 4.4 फीसद से घटकर, 4.3 फीसद हो जाना है। इस तरह के कुल सरकारी खर्च के दायरे में, जिसकी सीमाएं सरकार के एक ओर अमीरों पर कर बढ़ाने और दूसरी ओर राजकोषीय घाटा बढ़ने देने, दोनों से ही इंकार ने तय कर दी है, पूंजी व्यय में बढ़ोतरी की गयी है और इसका हिस्सा 2024-25 के जीडीपी के 4.0 फीसद तथा 2025-26 (संशोधित अनुमान) के 3.9 फीसद से बढ़कर, 2026-27 में 4.4 फीसद हो गया है।

**राज्यों पर बढ़ता हमला**

बहरहाल, पूंजी व्यय में यह बढ़ोतरी भी भ्रामक ही है। केंद्र सरकार का अपना पूंजी व्यय तो, जो 2023-24 में तथा 2024-25 में जीडीपी के 3.2 फीसद के बराबर था और 2025-26 (संशोधित अनुमान) में कुछ गिरकर 3.1 फीसद रह गया था, 2026-27 में 3.1 फीसद ही बना रहने जा रहा है। बढ़ोतरी होनी है, पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ग्रांट इन एड में, जो 2024-25 के 0.8 फीसद तथा 2025-26 के संशोधित अनुमान के 0.9 फीसद से बढ़कर, 2026-27 में 1.3 फीसद हो जानी है। लेकिन, इस आखिरी आइटम में मनरेगा का आवंटन भी शामिल है, जिसकी फंडिंग अब केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच, 60:40 के आधार पर साझा की जा रही होगी, जबकि पहले यह सहेदारी 90:10 के आधार पर ही हो रही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर राज्य सरकारें, जो पहले ही फंड की कमी से जूझ रही हैं, अपना आनुपातिक हिस्सा नहीं जुटा पाती हैं, जो जुटाना उनके लिए मुश्किल होगा, उस सूरत में केंद्र को भी मूल रूप में उसके द्वारा आवंटित हिस्सा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उस सूरत में केंद्र सरकार को बजट में दर्शाया गया खर्चा करना ही नहीं पड़ेगा और इसके ऊपर से वह इस कार्यक्रम की विफलता का दोष आसानी से राज्य सरकारों के सिर पर डालने में कामयाब हो जाएगी, जबकि इस योजना के व्यय के 60-40 के अनुपात में बंटवारे के फैसले में, राज्य सरकारें तो कहीं से शामिल ही नहीं थीं। यह फैसला तो एकतरफा तरीके से और पूरी तरह से मनमाने ढंग से केंद्र सरकार ने लिया था और उसे राज्यों पर तो थोप भर दिया गया था।

कथित ''सहकारी संघवाद'' की दिखावटी संज्ञा की यही हकीकत है। इसके नाम पर हो यह रहा है कि केंद्र सरकार मनमाने तरीके से राज्य सरकारों के संसाधनों तथा उनकी जिम्मेदारियों को तय कर रही है और इस तथ्य का इस्तेमाल अपने चहेते राज्यों को बढ़ावा देने के लिए कर रही है, जो इसके पक्षपाती होने के चलते जाहिर है कि भाजपा-शासित राज्यों के साथ पक्षपात के रूप में सामने आता है, जबकि गैर-भाजपा सरकारों के हाथ बांधे जाते हैं और फिर इन विपक्षी सरकारों पर कथित 'खराब प्रदर्शन' का दोष डाला जाता है। वाइवी रेड्डी की अध्यक्षता में, 14वें वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की थी कि करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा, 2020 तक पहले के 32 फीसद से बढ़कर 42 फीसद कर दिया जाए। लेकिन, केंद्र सरकार ने बाकायदा कर लगाने के बजाए, जिनकी प्राप्तियों को राज्यों के साथ साझा करना होता है, सैस तथा सरचार्ज लगाने का ही सहारा लिया, जिनकी प्राप्तियों को राज्यों के साथ साझा नहीं करना होता है और इस तरह उसने यह सुनिश्चित किया कि सैस तथा सरचार्ज समेत कुल कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा, 34 फीसद से ज्यादा हो ही नहीं पाए। यह व्यावहारिक रूप से केंद्र के हाथों में संसाधनों के केंद्रीकरण की ही एक अवैध तिकड़म है।

**पूंजी व्यय में बढ़ोतरी भ्रामक**

इस कपट लीला के बावजूद, केंद्र सरकार का व्यय जहां का तहां ही रहने जा रहा है (अगर जैसी कि हमने पीछे चर्चा की, पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता बजटीय प्रावधान से घटकर रहती है) या फिर जीडीपी के हिस्से के तौर पर उसमें मामूली सी बढ़ोतरी ही होने जा रही है। लेकिन, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के उन तीन फौरी संकटों पर काबू पाना संभव हो नहीं है, जिनकी हम शुरू में ही चर्चा कर आए हैं। वास्तव में समग्रता में केंद्र द्वारा पूंजी व्यय, जनता के हाथों में हस्तांतरणों के मुकाबले कम रोजगार पैदा करने वाला होता है। इसकी वजह यह है कि ढांचागत खर्च का मजदूरी का घटक, जोकि पूंजी व्यय के केंद्र में होता है, कुल पूंजी व्यय का एक अंश भर होता है। इसके विपरीत, जनता के लिए हस्तांतरित समूची राशि ही, व्यावहारिक मानों में एक प्रकार से मजदूरी के भुगतान का काम करती है। और जाहिर है कि अगर ढांचागत निवेश के लिए रखे गए संसाधनों को स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को लगाने आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन संस्थाओं में स्टाफ की भारी कमी है, या फिर इन संसाधनों का उपयोग सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में कर्मचारियों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उस सूरत में इस निवेश का रोजगार पर प्रत्यक्ष असर और इन नये रोजगार पाने वाले लोगों द्वारा पैदा की जा रही मांग के चलते द्वितीयक बहुगुणनकारी प्रभाव, कहीं ज्यादा उल्लेखनीय होगा। इसलिए, न सिर्फ यह कि यह बजट बेरोजगारी तथा गरीबी में बढ़ोतरी के रुझान को पलटने के लिए कुछ भी नहीं करता है, वास्तव में वह इससे उल्टा काम ही करता है। यह किया जाता है एक ओर तो निजी क्षेत्र को (और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों को भी) कर रियायतें देने के जरिए और दूसरी ओर प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने करने वाले खर्चों तथा जनता के पक्ष में हस्तांतरणों की कीमत पर, ढांचागत व्यय का अनुपात बढ़ाने के जरिए। ऐसा लगता है कि सरकार को इस सच्चाई का पता ही नहीं है कि निजी निवेश, बढ़ती मांग के प्रत्युत्तर में ही आता है। चाहे कितनी ही कर रियायतें क्यों न दी जाएं, पूंजीपतियों को निवेश बढ़ाने के लिए तब तक प्रेरित नहीं किया जा सकता है, जब तक पहले ही स्थापित उत्पादन क्षमता ठाली पड़ी रहती है। प्रसंगत- बता दें कि यही वजह है कि इससे पहले दी गयी तमाम कर रियायतों के बावजूद, जिनमें 2019 में कारपोरेट करों में कटौती करने जैसी भारी रियायतें भी शामिल थीं, निजी निवेश सुस्त ही बना रहा है। इसी तरह, एक ऐसे दौर में जब आम तौर पर विश्व अर्थव्यवस्था में तथा इसलिए निवेश में भी सुस्ती बनी हुई है, यह उम्मीद करना कि बहुराष्ट्रीय निगमों के करों के घटाए जाने भर से भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह चले आएंगी, बेतुकी बात है।

और इसकी उम्मीद तब करना जब ट्रंप अमेरिका से निवेशों को बाहर जाने से रोकने के लिए टैरिफ बढ़ाने के हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, और भी बेतुका है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने करन ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/[illegible])

# आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ वैदिक मूल्यों के चयन का दिया संदेश

## बीएमबीएल जैन वर्ल्ड स्कूल में स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन

मुरादाबाद।

बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास द्वारा बीएमबीएल जैन वर्ल्ड स्कूल के तत्वावधान में स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के कुल 259 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग कर अपनी शैक्षिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राजीव गुप्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे सशक्त माध्यम है।

शिक्षा न केवल ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण और जीवन-दृष्टि को भी सुदृढ़ करती है। उन्होंने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों की स्कूली शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बच्चों के लिए उपयुक्त विद्यालय का चयन और उनकी शिक्षा के अनुरूप सकारात्मक पारिवारिक एवं शैक्षिक वातावरण का निर्माण ही उनकी प्रतिभा को सही दिशा देने में सहायक होता है।

कार्यक्रम में कॉलेज के निदेशक सम्भव जैन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सही समय पर प्राप्त सही शिक्षा जीवन में सही मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि बच्चों के जीवन में पुस्तकों का जितना महत्व है, उससे कहीं अधिक महत्व उस परिवेश का है, जिसमें वे रहकर सीखते और विकसित होते हैं। जैसा वातावरण और संस्कार बच्चों को मिलते हैं, उनका व्यक्तित्व भी उसी अनुरूप विकसित होता है। उन्होंने कहा कि सभी अभिभावक और शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के लिए ऐसा प्रेरणादायी वातावरण तैयार करें, जहाँ आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ वैदिक शिक्षा प्रणाली और वैदिक मूल्यों का समन्वय हो। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं, बल्कि जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होना चाहिए। जब यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा क्यों आवश्यक है और वह हमें किस दिशा में आगे बढ़ाएगी, तभी जीवन एक सफल और सार्थक यात्रा बनता है। इस अवसर परप्रधानाचार्य राजीव गुप्ता, निदेशक सम्भव जैन सहित मेधाव्रत, मेधावी आर्य, संजय प्रकाश, उत्कर्ष, शैवाली वार्ष्णेय, अलका गुप्ता, सोनम यादव, रुचि वार्ष्णेय, नव्या गुप्ता, चंचल, शीतल, मनोज, कुश, नागेश, अखिलेश, नेत्रपाल, अंकित, अमित एवं अक्षय सहित विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। अंत में विद्यालय प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गई कि स्कॉलरशिप टेस्ट में सफल विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के आधार पर 100 प्रतिशत तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। परीक्षा का परिणाम विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन अनुशासित एवं प्रेरणादायी वातावरण में हुआ। विद्यालय प्रबंधन ने इस आयोजन को विद्यार्थियों की प्रतिभा पहचानने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

# सीडीओ ने किया कम्पोजिट विद्यालय का निरीक्षण

मुरादाबाद।

मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी ने विकास खण्ड छजलैट में स्थित कम्पोजिट विद्यालय सादकपुर खिचड़ी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कुल 105 नामांकित छात्र-छात्राओं के सापेक्ष 67 छात्र-छात्राएं उपस्थित मिले। विद्यालय में 01 इंचार्ज अध्यापक, 06 सहायक अध्यापक एवं 01 शिक्षामित्र उपस्थित थे। एक सहायक अध्यापक आकस्मिक अवकाश पर थे। उन्होंने विद्यालय की कक्षाओं में अध्ययनरत् बच्चों से उनके विषयों पर आधारित प्रश्न किये तथा उत्तर दिये जाने पर ब'चों को प्रोत्साहित किया। साथ ही अध्यापकों को निर्देशित किया कि विद्यालय में सभी ब'चे यूनीफार्म में उपस्थित हों। विद्यालय में पेड़-पौधे लगाने तथा छात्र उपस्थिति में वृद्धि करने के निर्देश दिए। विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र, जोकि जर्जर अवस्था में है, उसको विद्यालय में खाली एक कक्ष में स्थानान्तरित करने के निर्देश दिए। विद्यालय में स्थापित नक्षत्रशाला कक्ष की स्थिति संतोषजनक नही पाये जाने पर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

# संगठित होने से ही होगा समाज का विकास- विनोद गुप्ता

## राजनैतिक एवं सामाजिक स्तर पर पीछे है समाज-नारायण मुसाफा में हुई भारतीय दोसर वैश्य महासमिति की बैठक

फतेहपुर।

भारतीय दोसर वैश्य महासमिति की एक बैठक मुसाफा कस्बे में संपन्न हुई। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महासमिति के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद गुप्ता ने समाज के बंधुओं का उत्साहवर्धन करते हुये सभी को एक सूत्र में पिरोने के लिये कहा कि संगठित शक्ति से ही सामाजिक विकास संभव है। उन्होंने कहा कि सामाजिक उत्थान के लिये सभी को संगठन से जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा तभी हम सब संगठित हो पायेंगे। अध्यक्षता करते हुये जिलाध्यक्ष नारायण बाबू ने कहा कि मुसाफा कस्बे में काफी परिवार दोसर वैश्य समाज के निवास करते हैं मगर संगठित न होने के कारण राजनैतिक एवं सामाजिक स्तर से काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि मुसाफा कस्बे में 22 फरवरी को एक बड़ी बैठक आहूत की जायेगी जिसमें संगठन का गठन करते हुये सभी को जोड़ने का कार्य किया जायेगा। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील गुप्ता फौजी ने कहा कि संगठन एक विशाल वट वृक्ष की तरह होता है। उससे सभी को जोड़कर ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर दीपक गुप्ता, संजय गुप्ता, राजीव गुप्ता, सीताराम गुप्ता, अनुराग गुप्ता, राकेश गुप्ता, राहुल गुप्ता, राम, शिवधनी, कल्लू, धुन्नू, महावीर गुप्ता आदि रहे।

# अल जफीरा नूर ने डॉ कलाम साइंटिस्ट परीक्षा में कर्नाटक में स्वर्ण पदक प्राप्त कर बहराइच और यूपी का नाम किया रोशन

**बहराइच।** शहर के मोहल्ला नाजिरपुरा निवासी एवं सेवंथ डे इंटर कॉलेज की कक्षा 9 की छात्रा अल जफीरा नूर ने डॉ कलाम जूनियर साइंटिस्ट परीक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। ज्ञात हो कि डॉ कलाम जूनियर साइंटिस्ट परीक्षा की अंतिम परीक्षा दिल्ली स्थित शाहीन एकेडमी में आयोजित हुई। चार चरणों में आयोजित इस परीक्षा में 6 देशों- कतर, दुबई, सऊदी अरब,बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के छात्र सहित भारत के तीन लाख 30 हजार छात्र शामिल हुए थेद्य अंत में इस परीक्षा में 6 देश के केवल 25 छात्र-छात्राओं का चयन हुआ।जिसमें अल जफीरा नूर को छठा स्थान प्राप्त हुआ।उत्तर प्रदेश से इस परीक्षा में दो छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है।जिसमें से एक बहराइच निवासी अल जफीरा नूर व दूसरा पदक अलीगढ़ को मिला है। अल जफीरा नूर के पिता जावेद आलम ने बताया कि उनकी बेटी को शाहीन एकेडमी के मुख्यालय कर्नाटक में संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल कदीर द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।मालूम हो कि इससे पहले अल जफीरा नूर ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में संचालित जिला विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था तथा इंटरनेशनल

स्पेस ओलंपियाड- 2024 के तीन चरणों की परीक्षा को भी उत्तर किया थाद्यअल जाफिरा नूर को स्वर्ण पदक प्राप्त होने पर उनके परिजनों, शिक्षकों, शुभचिंतकों एवं कई सामाजिक संगठनों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

# जिला वॉलीबाल संघ,प्रयागराज की नई कार्यकारिणी घोषित

जिला वॉलीबाल संघ, प्रयागराज का चुनाव संपन्न

**मेजा,प्रयागराज** ।विगत दिवस डिस्ट्रिक्ट वॉलीबाल एसोसिएशन (डीवीए),प्रयागराज के आम सभा की विशेष बैठक (चुनावी मीटिंग) दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज गोसौराकलां,मेजारोड में 7 फरवरी 2026 को संपन्न हुई और संवैधानिक ढंग से आगामी 4 वर्षों (2026 - 30) तक के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी गुलशन शर्मा (जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रयागराज) एवं अन्य नामित पर्यवेक्षकों की देख-रेख में सरकार द्वारा क्रीडा संघों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार गुप्त मतदान प्रक्रिया के अंतर्गत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। जिसमें प्रभात कुमार राय को अध्यक्ष, आर.पी.शुक्ला को महासचिव तथा के.बी.एल श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए। उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वसम्मति से एक नई कार्यकारिणी समिति घोषित की गई,जो कि निम्नानुसार है सर्वश्री- जॉर्डन.एच.नाथ (चेयरमैन), सुशील कुमार मिश्रा (अधिवक्ता उच्च न्यायालय), भैयाराम यादव एडवोकेट, दुर्गेश प्रताप सिंह, विजया सिंह, एवं बर्फी लाल यादव (सभी उपाध्यक्ष), प्रमोद कुमार राय (संगठन मंत्री), नीरज श्रीवास्तव एवं मुकेश शुक्ला (संयुक्त मंत्री), तथा अल्ताफ अली, राजेश वर्मा, प्रभाकर चौबे, राजेश प्रसाद राय, पंकज शुक्ला व अजय कुमार राय सभी कार्यकारिणी सदस्य के पद पर चुने गए।

# किसान महाविद्यालय में आयोजित हुआ एनएमओ का मेगा स्वास्थ्य शिविर

बहराइच।

नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 के अंतर्गत नगर के किसान डिग्री कॉलेज परिसर में मेगा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक कौशल जी, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रांत प्रचारक कौशल किशोर ने कहा कि गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य यात्रा 2019 में प्रारंभ हुआ था, इस यात्रा के माध्यम से सीमावर्ती सुदूर क्षेत्रों में आयोजन कर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इन स्वास्थ्य कैंपों में 80 मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक छात्र भाग लेते हैं उन्होंने कहा की सेवा का कार्य पुनीत कार्य है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं उसका पुजारी हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्र में अन्य समस्याओं के बारे में भी जानकारी एकत्र कर लोगों को जागरूक करना है। मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री भाजपा संजय राय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह संघ की अद्भुत दृष्टि है कि बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेज छात्र सुदूर सीमावर्ती गांव में जाकर चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का मुख्य उद्देश्य सेवा है।

इसी मिशनरिया सेवा के माध्यम से लोग धर्मांतरण का कार्य करते थे किंतु गुरु गोरखनाथ सेवा यात्रा का उद्देश्य का नर सेवा नारायण सेवा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केवल शरीर की स्थिति नहीं यह शरीर एक साधना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेडिकल कॉलेज बहराइच के अध्यक्ष प्राचार्य डॉ संजय खत्री ने किया । कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर बृजेश शुक्ला डॉक्टर पुष्पेंश मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एनएमओ अध्यक्ष डॉ विजय कुमार, आरएमएल के सीएमएस डॉ विक्रम सिंह, निदेशक लोहिया संस्थान लखनऊ प्रोफेसर सी एम सिंह, सीएमओ डॉ संजय कुमार, निर्देशक जेएसबी हुंडई जतिन वर्मा, वाइस चेयरमैन सरदार पटेल डेंटल कॉलेज लखनऊ श्लोक सिंह, जिला अध्यक्ष डॉ सारिका साहू ने भी संबोधित किया। इस स्वास्थ्य शिविर में केजीएमयू, आरएमएल , एसजीपीजीआई, महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ-साथ जनपद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ एके तिवारी, डॉ संगीता मौर्य, डॉ पूजा जायसवाल , डॉ महेश अग्रवाल, डॉ मोहित अग्रवाल, डॉ के के वर्मा , डॉ रामराज यादव, डॉ त्रिलोकी विश्वकर्मा नेडॉ सानिध्य सिंह, डॉ नितिन मिश्रा, डॉ शिवम शुक्ला, डॉ अजय कुमार, डॉ राजकुमार डॉ राहुल विश्वकर्मा, वसुदेश डॉ सत्यम श्रीवास्तव, डॉ वैष्णवी, डॉ श्रेया राज भी मरीज का उपचार किया। इस स्वास्थ्य शिविर में संयोजक धर्मेंद्र सिंह,रमेश पाठक, सह विभाग संचालक कृष्णानंद, विभाग कार्यवाह अंबिका प्रसाद, जिला कार्यवाह भूपेंद्र, जिला प्रचारक अजय, डॉ विकास मिश्रा, डॉ मनीष शुक्ला, डॉक्टर दिव्येश बरनवाल, डॉ रामेंद्र त्रिपाठी, डॉ दिवाकर दत्त त्रिपाठी, डॉ उपेंद्र वर्मा ,डॉ प्रभात मिश्रा, डॉ पूजा, डॉ अमिताभ मिश्रा,डॉ सैफली गुप्ता,डॉ राम कुमार, विधायक सुभाष त्रिपाठी, एमएलसी पदम सेन चौधरी, सदर विधायक अनुपमा जायसवाल, जिला अध्यक्ष बृजेश पांडे विभाग प्रचारक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अतुल गौड़ आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर आए अतिथियों एवं मरीज के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया था।

# कमल फ्लाइट में होगा तो क्या वहां खोजेंगे, हमारे पास 50 काम; थानों में भटकते भाई को मिला ये जवाब

नई दिल्ली । भाई को ढूंढते परिजन एक पुलिस थाने से दूसरे थाने की चौखट पर भटकते रहे, लेकिन जवाब मिला क्या यही काम रह गया है। मंगोलपुरी से लेकर डाबड़ी और सागरपुर तक छह-सात थानों के चक्कर लगे, हर जगह पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली के डाबड़ी थाने में तो एक पुलिस कर्मी ने संवेदनहीनता की हद पार करते हुए कह दिया कि तुम्हारा भाई फ्लाइट में होगा तो वहां जाकर खोजो? हमारे पास 50 काम है, तुम्हारे भाई के लिए नहीं बैठे है। यह बात बिलखते हुए जनकपुरी में गड्ढे में गिरे कमल ध्यानी के भाई ने संवाद न्यूज एजेंसी से साझा की। रात 11:53 बजे कमल से आखिरी बात, बोला दस मिनट में घर पहुंच रहा हूं। 45 मिनट बीते, कमल ने परिजनों का फोन नहीं उठाया। बेचैन परिजन देर रात 12:45 बजे निकले, जनकपुरी, रोहिणी ऑफिस, हर जगह ढूंढा।

**कमल का फोन लग रहा था, लेकिन उठा नहीं**

विकासपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को बताया कि कमल का फोन लग रहा है, लेकिन उठ नहीं रहा। कृपया लोकेशन ट्रेस कर दीजिए। पुलिस ने टरकाते हुए बोला नाम-नंबर लिखवा दो हम देख लेंगे। अगर तुरंत फोन ट्रैक किया होता, तो शायद कमल की सांसें बच जातीं। परिजनों ने जनकपुरी थाने में शिकायत की। लोकेशन मिली, पार्क के पास। पुलिस ने व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजी लेकिन डिलीट भी कर दी। मृतक का भाई करन वहां पहुंचा, अंधेरे में देखे, चीखते आवाज देता रहा लेकिन भाई नहीं मिला। 112 पर कॉल करने पर पहुंची पुलिस ने टका सा जवाब दिया क्या हम झमेलिए है? यह दिल दहलाने वाला रवैया देश की सबसे हाईटेक पुलिस का दंभ भरने वाली दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से खोदे गए गड्ढे में बाइक सवार कमल ध्यानी के गिरने की सूचना अधिकारियों को नहीं देने के आरोप में उप-ठेकेदार राजेश कुमार प्रजापति (47) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गार्ड योगेश को भी तलाश रही है, जिसने घटना की जानकारी उप ठेकेदार को दी थी। हादसे के बाद से वह लापता है। इस बीच, कमल के परिजनों ने पुलिस और जल बोर्ड के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) दराडे शरद भास्कर ने बताया कि जांच में पता चला कि पुलिस के पता चलने से पहले उप ठेकेदार राजेश कुमार को पता था कि कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर गया है। पुलिस के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शी विपिन सिंह ने बाइक सवार को गड्ढे में गिरते देखा तो रैन के सुरक्षा गार्ड को सूचना दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गार्ड ने तुरंत योगेश नामक गार्ड को बताया, जिसने देखा कि गड्ढे में कोई गिरा है। योगेश ने रात करीब 12:22 बजे राजेश को सूचना दी। राजेश मौके पर तो पहुंचा, लेकिन न तो उसने पुलिस को सूचित किया न आपातकालीन प्राधिकरण को जानकारी दी। उपायुक्त भास्कर ने बताया कि यूपी निवासी योगेश और गार्ड को पुलिस तलाश रही है। घटनाक्रम का सटीक पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला शांत भी नहीं हुआ कि अब राजधानी दिल्ली में जल बोर्ड की ओर से खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जनकपुरी की बी-ब्लॉक में 20 फीट गहरे गड्ढे में बृहस्पतिवार रात गिरे युवक ने मदद न मिलने पर तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। जनकपुरी थाने में ठेकेदार और जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

## जनकपुरी हादसा : श्रद्धांजलि देने पहुंचे सौरभ भारद्वाज समेत कई क्रनेता हिरासत में, पुलिस पर तानाशाही के आरोप

नई दिल्ली । दिल्ली के जनकपुरी में 25 वर्षीय कमल ध्यानी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को कैंडल मार्च के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आप नेताओं ने पुलिस पर धक्का-मुक्की, पोस्टर फाड़ने और शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम को जबरन रोकने के आरोप लगाए। आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में विधायक जरनैल सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता जनकपुरी के उसी गड्ढे के पास पहुंचे थे, जहां कमल ध्यानी की गिरकर मौत हुई थी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पुलिस ने मोमबत्ती तक जलाने नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी तत्परता पुलिस ने नेताओं को रोकने में दिखाई, अगर उतनी ही युवक को बचाने में दिखाई होती तो आज कमल ध्यानी जिंदा होते। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हादसे की रात कमल ध्यानी का परिवार और दोस्त पूरी रात छह अलग-अलग थानों में शिकायत दर्ज कराने के लिए भटकते रहे, लेकिन किसी भी थाने ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले मोबाइल लोकेशन साझा की और फिर उसे डिलीट कर दिया। समय रहते कार्रवाई होती तो युवक की जान बच सकती थी। उन्होंने मांग की कि सरकार कमल ध्यानी को न्याय दिलाए और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

# गौरव गोगोई गुपचुप पाकिस्तान गए थे, किसी तरह की ट्रेनिंग भी ली; सीएम बिस्वा सरमा का बड़ा आरोप

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से कथित संबंधों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि गौरव गोगोई 2013 में बिना जानकारी दिए पाकिस्तान गए थे और वहां किसी तरह का प्रशिक्षण लिया गया हो सकता है। इस मामले की जांच अब केंद्रीय एजेंसी से कराने की तैयारी है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि गौरव गोगोई 2013 में गुपचुप तरीके से पाकिस्तान गए थे और इसकी जानकारी भारतीय अधिकारियों को नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि आशंका है कि इस दौरान गोगोई ने वहां किसी प्रकार का प्रशिक्षण लिया हो। मुख्यमंत्री ने यह बयान विधानसभा चुनावों से पहले दिया है

हिमंता बिस्वा सरमा ने गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई पर भी गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री का दावा है कि एलिजाबेथ भारत में एक संस्था में काम करते हुए देश से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर पाकिस्तान भेजती थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एलिजाबेथ दो भारतीय संस्थाओं में काम करते हुए नौ बार पाकिस्तान गई थीं। असम सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख, गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के कथित भारत-विरोधी षड्यंत्र की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। एसआईटी ने 10 सितंबर को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। रिपोर्ट के बाद असम कैबिनेट ने फैसला किया कि मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी

**मामले की जांच अब केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताया जा रहा है यह पूरा विवाद।**

चाहिए। अब यह केस गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक वायरल तस्वीर का भी जिक्र किया, जिसमें गौरव गोगोई युवाओं के साथ पाकिस्तान दूतावास जाते दिखे थे। उस समय भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित थे। हिमंता ने कहा कि इस तरह की गतिविधि से पाकिस्तान को वैधता देने की कोशिश की गई। उन्होंने यह भी कहा कि एलिजाबेथ ने पाकिस्तान में 18 मार्च 2011 से 17 मार्च 2012 तक काम किया था और इस दौरान उनके अली तौकीर शेख से करीबी संबंध बने।

**अली तौकीर शेख पर सवाल**

मुख्यमंत्री ने अली तौकीर शेख को पर्यावरणविद मानने से इनकार किया।

उनका आरोप है कि शेख सिंधु जल संधि और भारत-पाकिस्तान विवाद से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तान के पक्ष में काम कर रहे थे। एसआईटी रिपोर्ट में अली तौकीर शेख, एलिजाबेथ गोगोई और गौरव गोगोईतीनों के पाकिस्तान से सीधे संबंध होने का दावा किया गया है।

**कांग्रेस का जवाब**

इस पूरे विवाद पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पहले ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के आरोपों को निराधार बता चुके हैं। गोगोई का कहना है कि यह आरोप मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। फिलहाल, मामला केंद्र सरकार के पास भेजे जाने की प्रक्रिया में है।

## भागे नहीं, संघर्ष करें... बांग्लादेशी हिन्दुओं को मोहन भागवत की सलाह

मुंबई । आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा पर कड़ा और साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वहां के हिंदुओं को अकेले पड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का हिंदू समाज उनके समर्थन में खड़ा है। मुंबई के नेहरू सेंटर में संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक लेक्चर में भागवत जी ने कहा, बांग्लादेश में करीब सवा करोड़ (1.25 करोड़) हिंदू हैं। अगर वे वहीं रहकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला करते हैं तो दुनिया भर के सभी हिंदू उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। यह सब अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद शुरू हुआ। इस तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए।

## राजधानी में बड़ी घटना: दिल्ली में कार के अंदर मिलीं तीन लाशें, दो पुरुष, एक महिला; फ्लाई ओवर पर खड़ी थी गाड़ी

नई दिल्ली । दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाई ओवर पर एक कार से तीन लोगों के शव बरामद हुए है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक, कार टवेरा थी और उसमें से तीन लोगों के शव मिले है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, फायर टीम को लावारिस कार मिलने की सूचना मिली थी। टीम जब मौके पर पहुंची तो कार में तीन लोग मृत पाए गए ,जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की छानबीन शुरू की गई है। कार में संदिग्ध हालात में तीनों की मौत हुई है और मृतकों की पहचान हो गई है। मृतकों में एक महिला और दो पुरुषों के शव मिले है। जिन लोगों के शव मिले, उनकी पहचान रणधीर सिंह (60 वर्ष), लक्ष्मी सिंह (40 वर्ष) और शिव नारायण (46 वर्ष) के रूप में हुई है। डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में डेडबॉडी हो सकती है। यहां पर जब आकर देखा तो तीन लोग डेड थे। उनकी पहचान कर ली गई है। हम मामले की जांच कर रहे है। हालही में दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय की हत्या का भी मामला सामने आया था। दिल्ली के पांडव नगर के आचार्य निकेतन इलाके में एक डिलीवरी बॉय को चाकू से गोदकर मारा गया था। इस मामले में तीन नाबालिग पकड़े गए थे। मृतक के शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे, जिसमें मृतक के गले और सीने में भी कई बार हमला किया गया था। मृतक की उम्र महज 22 साल थी और उसकी पहचान अरुण राज के रूप में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने बताया था कि तीन युवक बाइक से आ रहे थे, इसी दौरान उनका डिलीवरी बॉय से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि नाबालिग आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी, जिसकी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।

# सूरजकुंड मेलाहादसा : सीएम सैनी ने इंस्पेक्टर के परिवार के सदस्य को नौकरी, घायलों को 1 लाख मुआवजे का एलान

फरीदाबाद । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने रविवार को सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की बहादुरी की तारीफ की और उनके परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। शनिवार की शाम सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में खुशियों का माहौल तब मातम में बदल गया जब सुनामी नाम का एक झूला अचानक टूट गया।

उस वक्त झूले पर करीब 19 लोग सवार थे। झूला हवा में ही एक तरफ झुक गया और फिर सीधा जमीन पर आ गिरा। इस हादसे में कई लोग घायल हुए और राहत कार्य के दौरान एक पुलिस अधिकारी की जान चली गई। पलवल में तैनात इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद मेले में ड्यूटी पर थे। जैसे ही झूला गिरा, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। इसी दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। जगदीश प्रसाद 1989 में पुलिस में भर्ती हुए थे। 36 साल की सेवा के बाद वे इसी साल मार्च में रिटायर होने वाले थे।

**जान गंवाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की बहादुरी की तारीफ की और उनके परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया।**

**मुख्यमंत्री सैनी ने क्या कहा?**

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हादसे की खबर मिलते ही पर्यटन मंत्री और बड़े अधिकारियों को मौके पर भेजा गया था। उन्होंने कहा कि शहीद इंस्पेक्टर के परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा दी जाएगी। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाही की पुलिस ने झूला चलाने वाले (संचालक) और उसके कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (धारा 105) का केस दर्ज किया गया है। मामले की गहराई से जांच के लिए एक विशेष जांच टीम बनाई गई है।

## शिवसेना यूबीटी और मनसे के दबाव में भाजपा ने रितु तावड़े को मुंबई का मेयर चुना- संजय राउत

मुंबई । शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी और मनसे को मराठी लोगों की ओर से मिले भारी समर्थन के कारण ही भाजपा को मुंबई के लिए एक मराठी मेयर चुनना पड़ा। शनिवार को संघ के शताब्दी समारोह में फिल्म अभिनेता सलमान खान को मोहन भागवत से बातचीत करते देखा गया। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने इसे लेकर संघ पर निशाना साधा। राज्यसभा सदस्य राउत ने पूछा, क्या यह बॉलीवुड स्टार सलमान खान का स्वागत था या संघ और उसकी शाखाओं में मुसलमानों का भी स्वागत है? उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से हिंदू- मुस्लिम नफरत और बदले की भावना वाला प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। संघ भी इसका हिस्सा है, ऐसे में भागवत को इस बारे में साफ करना चाहिए था। भाजपा द्वारा मुंबई मेयर पद के लिए रितु तावड़े (53) को नामांकित करने पर संजय राउत ने कहा कि वह मूल रूप से कांग्रेस की हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के पास अपना कुछ भी असली नहीं है। उन्होंने कहा, जिस तरह से मराठी लोगों ने शिवसेना यूबीटी और मनसे को भारी संख्या में वोट दिया, उसके चलते भाजपा को मुंबई में एक मराठी मेयर बनाना पड़ा। तावड़े का मुंबई की मेयर बनना लगभग तय है और वे बीते चार दशकों में भाजपा की पहली मेयर होंगी। शिवसेना यूबीटी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है, जिससे मुकाबला निर्विरोध हो गया और देश के सबसे अमीर नागरिक निकाय पर ठाकरे परिवार का 25 साल का दबदबा खत्म हो गया।

## पंजाब में इन्वेस्टर्स समिट से पहले सीएम मान को झटका, केंद्र ने यूरोप दौरे पर लगाई रोक

**आप भड़की**

पंजाब । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नीदरलैंड और चेक गणराज्य का दौरा रद्द हो गया है। इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार ने उनके पॉलिटिकल क्लीयरेंस के अनुरोध को रोक दिया और उनके दौरे पर कोई जवाब नहीं दिया। यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री मान को विदेश जाने से रोका गया हो। पिछले कुछ समय में यह तीसरी बार है जब उन्हें मंजूरी नहीं मिली। इससे पहले पिछले महीने ही उन्हें निवेश के सिलसिले में यूके और इजराइल में जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। इससे पहले पेरिस ओलंपिक के दौरान भारतीय हॉकी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके फ्रांस जाने के अनुरोध को भी केंद्र ने मना कर दिया था। अगले महीने पंजाब में इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है। मुख्यमंत्री मान एक

डेलिगेशन के साथ यूरोप के इन देशों में जाकर बड़े बिजनेसमैन से मिलना चाहते थे, ताकि पंजाब में विदेशी निवेश लाया जा सके और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बना रही है। इस तरह की पाबंदियों से पंजाब के विकास और निवेश लाने की कोशिशों को नुकसान पहुंच रहा है। जब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री विदेश जा सकते हैं, तो पंजाब के मुख्यमंत्री को बार-बार क्यों रोका जा रहा है? नियमों के मुताबिक, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। हालांकि, मंत्रालय अक्सर मंजूरी न देने का कोई खास कारण सार्वजनिक रूप से नहीं बताता, जिससे यह मामला अब एक राजनीतिक विवाद बन गया है।

## भारत सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती, नक्सली हथियार डाल दें, रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करेंगे- शाह

रायपुर । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद को लेकर उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही राज्य में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, CRPF, NIA, BSF, ITBP के महानिदेशक सहित छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा-केंद्रित रणनीति, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर कड़ा प्रहार और प्रभावी आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि 31 मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरह नक्सल-मुक्त हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि कभी नक्सली हिंसा का गढ़ रहा छत्तीसगढ़, आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के चलते विकास का पर्याय बन चुका है। गृह मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के युवा अब खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ रहे है और अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद ने देश की कई पीढ़ियों को गरीबी और अशिक्षा के अंधकार में धकेला, लेकिन अब देश इस अभिशाप से मुक्ति के बेहद करीब है। मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि माओवाद के खिलाफ लड़ाई बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए और केन्द्र व राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि बचे हुए नक्सली एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग न सकें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विकास के समान अवसर मिलें।

# आतंकवाद पर भारत का संदेश साफ है, कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं, मलेशिया से पीएम मोदी का पाकिस्तान को संदेश

नई दिल्ली । अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान मलेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच से आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर शंखनाद किया है। रविवार (8 फरवरी, 2026) को मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में पीएम मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए सख्त रुख अपनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा, ''आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है: कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं।'' मोदी शनिवार को कुआलालंपुर पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर इब्राहिम ने उनका स्वागत किया जो द्विपक्षीय संबंधों में एक नयी गति का संकेत है। वार्ता से पहले मोदी का आज सुबह पर्दाना पुत्र में औपचारिक स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कहा, ''भारत और मलेशिया के बीच एक विशेष संबंध है। हम समुद्री पड़ोसी हैं। सदियों से दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे और स्नेहपूर्ण संबंध रहे हैं।''

उन्होंने कहा, ''आज, भारतीय मूल के लोगों की आबादी के मामले में मलेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्य हमें एक सूत्र में बांधते हैं।'' मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष आतंकवाद विरोधी उपायों, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम रक्षा सहयोग को और अधिक व्यापक बनाएंगे। उन्होंने कहा, ''कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ हम सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे।'' प्रधानमंत्री ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ''हिंद-प्रशांत क्षेत्र विश्व के विकास के इंजन के रूप में उभर रहा है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई देशों का संघ) के साथ मिलकर पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम ने कहा कि भारत और मलेशिया व्यापार, निवेश, संपर्क और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर भारत ने शानदार वृद्धि दर्ज की है।

## खुले मैदान में गिरा ट्रेनिंग विमान; क्रैश से पहले बाहर कूदे पायलट और यात्री, सभी सुरक्षित

बंगलूरू। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के बालेश्वर तालुक के मालूर गांव में रविवार दोपहर एक प्राइवेट मिनी विमान खुले मैदान में क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत दोनों यात्री बाल-बाल बच गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, रेड बर्ड कंपनी का यह दो-सीटर ट्रेनिंग विमान था। क्रैश से ठीक पहले दोनों यात्री विमान से बाहर निकलने में सफल रहे। टक्कर के बाद विमान तीन हिस्सों में टूट गया। हादसे में दोनों को चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यह ट्रेनिंग विमान कलबुर्गी से बेलगावी की ओर जा रहा था। हालांकि, दुर्घटना के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही है।